

डिप्टी कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स आदि आदि

बनाम

ए. बी. इस्माइल आदि आदि

15 अप्रैल, 1986

[पी.एन.भगवती, मुख्य न्यायाधिपति, वी.खालिद और जी.एल.ओजा, जे.जे.]

केरल सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1963: धारा 5 - ए (1) (ए) बकरियों और भेड़ों के वध के बाद उत्पादित मटन - क्या 'अन्य सामान' पर कर निर्धारण योग्य है।

शब्द और वाक्यांश: "बकरी और भेड़" और "मटन" का अर्थ।

केरल सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1963 की धारा 5-ए(1)(ए) एक डीलर के खरीद टर्नओवर पर खरीद कर लगाने का प्रावधान करती है जो अपने व्यवसाय के दौरान सामान खरीदता है, जिसकी बिक्री या खरीद उत्तरदायी है। उस अधिनियम के तहत कर लगाने के लिए, उन परिस्थितियों में जिनमें धारा 5 के तहत कोई कर देय नहीं है और फिर बिक्री के लिए या अन्यथा अन्य वस्तुओं के निर्माण में ऐसे सामान का उपभोग करता है।

उत्तरदाता वध के लिए बकरियों और भेड़ों को खरीदते हैं और फिर वध के बाद प्राप्त मांस को बेचते हैं। धारा 5-ए (1)(ए) के तहत उनकी बकरियों और भेड़ों की खरीद के कारोबार पर बिक्री कर का मूल्यांकन

अधिकारी द्वारा इस धारणा पर किया गया था कि उन्होंने वध की विनिर्माण प्रक्रिया द्वारा जानवरों को मांस में बदल दिया। अपीलीय अधिकारी और न्यायाधिकरण मूल्यांकन अधिकारी से सहमत थे।" हालांकि, उच्च न्यायालय ने मूल्यांकन आदेशों को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि जानवरों के वध के बाद प्राप्त मांस धारा के अर्थ में 'अन्य सामान' नहीं था।

विभाग द्वारा प्रमाण पत्र द्वारा इन अपीलों में उत्तरदाताओं के लिए यह तर्क दिया गया था कि वे केवल जीवित बकरी और भेड़ को मारकर और उन्हें टुकड़ों में काटकर मटन में संसाधित कर रहे थे और इस प्रक्रिया में न तो खपत होती थी, न ही निर्माण, न ही 'अन्य सामान' का उत्पादन होता था।

न्यायालय द्वारा अपीलों को स्वीकार करते हुए, अभिनिर्धारित किया गया :-

1. केरल सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1963 की धारा 5-ए(1)(ए) हैं के तीन अवयव हैं: (1) माल की खपत; (11) निर्माण की प्रक्रिया शामिल है, और (111) मूल वस्तुओं से अलग अन्य वस्तुओं का उत्पादन।
[525 बी]

2. जब बकरियों और भेड़ों को मांस में परिवर्तित किया जाता है, तो अधिनियम धारा 5-ए(1)(ए) के अर्थ में "अन्य सामान" अस्तित्व में आया,

क्योंकि जानवरों का वध और उनका मांस में रूपांतरण बकरियों और भेड़ों की खपत का परिणाम है, जिसमें निर्माण की प्रक्रिया का भी अनुमान लगाया जा सकता है। [525 एफ-जी]

3. वाणिज्यिक हल्को में और आम बोलचाल में "बकरियां और भेड़" और "मटन" दो अलग-अलग चीजें हैं जिनकी अपनी अलग पहचान है, एक दूसरे से अलग है, क्योंकि जब बकरियों और भेड़ों को वध की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तो मांस, खाल और खाल मूल वस्तुओं से पूरी तरह से अलग हैं, उक्त प्रक्रिया में जानवरों को खाकर उत्पादित की जाती हैं। [525 ई; 527 एफ]

मौजूदा मामले में उच्च न्यायालय ने यह मानने में गलती की कि "माल" और "मांस" एक ही थे और बकरियों को मांस में बदलने में कोई खपत शामिल नहीं थी। [529 ई-पी]

के.चेयब्बा बनाम कर्नाटक राज्य, [1980] 45 एस.टी.सी. 1, स्वीकृत।

अनवर खान महबूब बनाम बॉम्बे राज्य, [1960] 1 एस.टी.सी. 698
- संदर्भित किया गया।

डिप्टी कमिश्नर, सेल्स-टैक्स (कानून) बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (टेज़) एर्नाकुलस बनाम पियो फूड पैकर्स, [1980] 3 एस.सी.आर. 1271 और चिरंजीत लाल आनंद बनाम असम राज्य और अन्य, [1985] ए.आई.आर. एस.सी. 1387, अंतर किया गया ।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 1161/1979
आदि।

केरल उच्च न्यायालय,टी.आर.सी. संख्या 130/1977 में पारित अंतिम
निर्णय और आदेश दिनांक 13.6.1978 से।

के.एम.के. नायर, अपीलकर्ताओं के लिये ।

एन. वीरप्पा, वी.जे. फ्रांसिस और एस. बालकृष्णन, प्रतिवादियों के
लिये।

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति खालिद,जे. द्वारा पारित किया
गया :-

1. केरल उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ के फैसले के खिलाफ इन
अपीलों में प्रमाणपत्र द्वारा तय किया जाने वाला संक्षिप्त प्रश्न यह है कि
क्या बकरी और भेड़ और उनके वध के बाद प्राप्त मांस राज्य में बिक्री कर
इस उद्देश्य के लिए समान हैं। उच्च न्यायालय ने बिक्री-कर अपीलीय
न्यायाधिकरण से असहमति जताते हुए उन्हें वही सामान माना।

2. इन अपीलों में यह स्वीकार किया गया मामला है कि उत्तरदाता
वध करने के लिए बकरी और भेड़ खरीदते हैं और फिर ऐसे वध के बाद
प्राप्त मांस को बेचते हैं। यह भी स्वीकार किया गया है कि पशुधन केरल
सामान्य बिक्री-कर अधिनियम (संक्षेप में अधिनियम) के अर्थ के अंतर्गत
माल होगा।उत्तरदाताओं ने मांस और त्वचा की बिक्री पर छूट का दावा

करते हुए शून्य रिटर्न जमा किया। इन शून्य रिटर्न को स्वीकार करते हुए मूल्यांकन पूरा किया गया। इसके बाद करदाताओं को सूचित किया गया कि बकरियों और भेड़ों का खरीद कारोबार अधिनियम की धारा 5-ए के तहत कर लगाने से बच गया है। आवश्यक सुनवाई के बाद, मूल्यांकन आदेश पारित किए गए, जिसमें कहा गया कि करदाताओं ने अधिनियम की धारा 5-ए के अर्थ के तहत, विनिर्माण प्रक्रिया द्वारा जानवरों को मांस में बदल दिया। अपीलीय अधिकारी और न्यायाधिकरण मूल्यांकन अधिकारी के इस निष्कर्ष से सहमत थे। निर्धारिती ने मामले को उच्च न्यायालय के समक्ष उठाया और मूल्यांकन आदेशों को चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने मूल्यांकन आदेशों को रद्द कर दिया और माना कि जानवरों के वध के बाद प्राप्त मांस धारा 5-ए के अर्थ में 'अन्य सामान' नहीं होगा। इसलिए राज्य द्वारा ये अपीलें।

3. इन मामलों में उठाए गए विवाद की उचित समझ के लिए अधिनियम की धारा 5-ए(1)(ए) को पढ़ना आवश्यक है जो अकेले ही हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है।

"5. खरीद कर का उद्ग्रहण: (1) प्रत्येक व्यापारी जो अपने व्यवसाय के दौरान किसी पंजीकृत व्यापारी या किसी अन्य व्यक्ति से कोई सामान खरीदता है, जिसकी बिक्री या खरीद इस अधिनियम के तहत कर के लिए उत्तरदायी है,

परिस्थितियों में जिस पर धारा 5 के तहत कोई कर देय नहीं है, और या तो -

(ए) बिक्री के लिए या अन्यथा अन्य वस्तुओं के निर्माण में ऐसे माल का उपभोग करता है;"

धारा तीन सामग्रियों की बात करती है, जिनके अस्तित्व पर ही कर लगाया जाएगा, वे हैं: (1) वस्तुओं की खपत (11) शामिल निर्माण की प्रक्रिया और (iii) अन्य वस्तुओं का उत्पादन। हमारे सामने सवाल यह है कि क्या ये सामग्रियां तब मौजूद होती हैं जब बकरियों और भेड़ों का वध किया जाता है और उन्हें बिक्री के लिए मांस में परिवर्तित किया जाता है। निर्धारिती का तर्क यह है कि वह केवल जीवित बकरी या भेड़ को मारकर और उन्हें टुकड़ों में काटकर मटन बनाने का प्रसंस्करण कर रहा है और इस प्रक्रिया में न तो खपत होती है, न ही विनिर्माण होता है और न ही "अन्य वस्तुओं" का उत्पादन होता है।

4. बार में उद्धृत प्रस्तुतियों से निपटने से पहले, अधिकारियों की सहायता के बिना, इस सवाल पर विचार करना उपयोगी होगा कि क्या 'बकरियां और भेड़' और 'मटन' वही सामान हैं जो वाणिज्यिक हलकों और आम बोलचाल में जाने जाते हैं। हम देखेंगे कि एक आम आदमी इन भावों को कैसे समझता है। यदि कोई व्यक्ति कसाई की दुकान पर जाकर मिट्टन मांगता है तो उसे बकरियां नहीं दी जाएंगी और न ही वह बकरों से

संतुष्ट होगा। इसी तरह जब वह बकरियां खरीदने का इरादा रखता है तो उसे मांस भी दे दिया जाए तो वह संतुष्ट नहीं होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों, वाणिज्यिक हल्को में और आम बोलचाल में, दो अलग-अलग चीजें हैं जिनका अपना एक अलग व्यक्तित्व है, एक दूसरे से अलग है। इसलिए यह मान लेना गलत होगा, जैसा कि उच्च न्यायालय ने किया है, कि ये दोनों सामान एक ही हैं। होता यह है कि जब बकरियाँ और भेड़ें मांस में परिवर्तित हो जाती हैं, तो धारा के अर्थ में "अन्य सामान" अस्तित्व में आते हैं। यह सच है कि धारा 5-ए को आकर्षित करने के लिए, दो अन्य सामग्रियों को भी संतुष्ट करना होगा, अर्थात् उपभोग और निर्माण। उपभोग व्यापक आयात का शब्द है। यह किसी चीज़ को ग्रहण करने, उस चीज़ को दूसरे में परिवर्तित करने को दर्शाता है। यहां जानवरों का वध करना और उन्हें मांस में बदलना कानूनी दृष्टि से बकरियों की खपत का परिणाम है। ऐसे रूपांतरण में निर्माण की एक प्रक्रिया का भी अनुमान लगाया जा सकता है। बेशक, इस धारा का महत्वपूर्ण तत्व उपभोग और निर्माण के बाद अन्य वस्तुओं को अस्तित्व में लाना है, जो मूल वस्तुओं से अलग हैं। बेजान मटन, किसी भी मानक के अनुसार, "बकरी और भेड़" से अलग "अन्य सामान" है।

5. उच्च न्यायालय ने अपना निष्कर्ष उच्च न्यायालय के उसी एक निर्णय 41 एस.टी.सी. 364 में प्रकाशित पर रखा। विस्तृत चर्चा के बिना,

उच्च न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय पर भरोसा करते हुए इस प्रकार निर्णय लिया:

".....हमने मामले पर अपना सावधानीपूर्वक ध्यान दिया है; और हमने लेन-देन में शामिल प्रक्रियाओं और विशेष रूप से अनुभाग के प्रावधानों के आलोक में उनके प्रभाव के संबंध में विस्तृत तर्कों पर फिर से सावधानीपूर्वक विचार किया है। चूँकि हममें से कोई भी पहले की खंडपीठ के फैसले में पक्षकार नहीं था। हमारा स्पष्ट मानना है कि न्यायधिकरण ने जो दृष्टिकोण अपनाया, उसमें वह सही नहीं था और यह नहीं कहा जा सकता कि इसके परिणामस्वरूप कोई "उपभोग" हुआ। अनुभाग के अर्थ के अंतर्गत "अन्य वस्तुओं" का "निर्माण".....

इसके बाद उच्च न्यायालय ने 207 यूएस 556 में रिपोर्ट किए गए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय और 20 एस.टी.सी. 261 व 40 एस.टी.सी. 350 में रिपोर्ट किए गए निर्णयों का उल्लेख किया और इस प्रकार माना गया:

".....व्यावसायिक अर्थ में, अर्थात् वाणिज्यिक जगत को ज्ञात अर्थ में, हमें नहीं लगता कि बकरियों या भेड़ों को काटने या वध करने के बाद बाजार में बिक्री के लिए रखे

गए मांस के बारे में कहा जा सकता है बकरी या भेड़ को 'खाने' के बाद 'निर्मित' किया गया है। बिक्री के लिए रखा गया मांस अभी भी बकरी या भेड़ का है, उसी तरह जैसे कि तैयार चिकन अभी भी चिकन है, या कटा हुआ, डिब्बाबंद और पैक किया हुआ अनानास अभी भी तैयार किया हुआ अनानास है इसे विपणन योग्य बनाने के लिए अल्पतम प्रक्रिया के बाद कच्चे फल से.....”

हम यह मानने के लिए बाध्य हैं कि मामले के तथ्यों के प्रति उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण गलत था और ऊपर उल्लिखित निर्णयों पर निर्भरता गलत थी। अमेरिका के मामले में सवाल यह था कि क्या चिकन को उसके पंख उखाड़ने और उसकी अंतड़ियों को बाहर फेंकने के बाद मार डाला गया और कपड़े पहना दिया गया और कोल्ड स्टोरेज में फेंक दिया गया, क्या यह एक निर्मित उत्पाद था, जो चिकन से अलग था। वहां की अदालत ने माना कि चिकन को मार दिया गया और कपड़े पहना भी चिकन ही है। हम सम्मानपूर्वक इस निष्कर्ष से सहमत हैं। एक मरा हुआ चिकन और कपड़े पहना चिकन भी, दोनों चिकन मुर्गे ही है और दोनों को आम आदमी के साथ-साथ व्यावसायिक जगत भी चिकन के नाम से जानता है। पंखों और अंतड़ियों को हटाकर तैयार चिकन को मेज के लिए तैयार किया जाता है। मूल माल से भिन्न किसी वस्तु के निर्माण और उसे अस्तित्व में लाने की कोई प्रक्रिया नहीं है। 20 एस.टी.सी. 261 में

न्यायालय को कच्चे झींगे से बने झींगा गूदे से निपटना था। कोर्ट ने माना कि झींगा गूदा बनाने में न तो खपत थी और न ही निर्माण और रूपांतरण की प्रक्रिया में, जब झींगा गूदा अस्तित्व में आया तो कच्चे झींगा से अलग सामान का उत्पादन नहीं किया गया था। 41 एस.टी.सी. 364 में, इसमें शामिल सामान अनानास और अनानास के कटे हुए टुकड़े थे। वे स्पष्ट रूप से वही सामान हैं। इस न्यायालय ने इस निष्कर्ष को मंजूरी दे दी जब राज्य ने इस न्यायालय के समक्ष अपील में मामला उठाया।

6. यह न्यायालय अंसार खान महबूब बनाम बॉम्बे राज्य, [1960] 11 एस.टी.सी. 698 में आयोजित किया गया था कि तने और धूल को हटाकर कच्चे तम्बाकू को बीड़ी में बदलना, जो बदले में बीड़ी के निर्माण के लिए आवश्यक है, कच्चे तम्बाकू की खपत के समान है जिस पर कर देयता लगती है। कमोबेश यही स्थिति हमारे सामने है। बकरियों को मिट्टन में परिवर्तित करने में स्पष्ट रूप से उपभोग की एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा मूल वस्तुओं से भिन्न वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है।

7. कर्नाटक उच्च न्यायालय को एक समान प्रश्न पर विचार करना था जैसा कि अब हमारे सामने के. चेयब्बा बनाम कर्नाटक राज्य, [1980] 45 एस.टी.सी.1 कर्नाटक बिक्री-कर अधिनियम, 1957 की धारा 6 के संदर्भ में उठाया गया था। न्यायालय ने माना कि उस मामले में डीलर

जिन्होंने अपने व्यवसाय के दौरान उन परिस्थितियों में भेड़ और बकरी खरीदी थी जिनमें उस अधिनियम की धारा 5 के तहत कोई कर नहीं लगाया जा सकता था, अधिनियम की धारा 6 के तहत खरीद मूल्य पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे, क्योंकि वे अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के हिस्से के रूप में मटन, खाल और खाल का उत्पादन करने के लिए बकरियों और भेड़ों को मारकर उनका उपभोग करते थे। हम इस मामले में निष्कर्ष को मंजूरी देते हैं।

8. उत्तरदाताओं ने डिप्टी कमिश्नर, सेल्स-टैक्स (कानून) बोर्ड ऑफ रिवर्स (टैक्स) एर्नाकुलम बनाम पियो फूड पैकर्स, [1980] 3 एस.सी.आर. 1271 के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया। उस मामले में इस न्यायालय ने निर्धारिती की इस दलील को बरकरार रखा कि कच्चे अनानास को जब टुकड़ों में बदला जाता है, तो उसकी पहचान नहीं बदलती है, ताकि कर के दायित्व को आकर्षित किया जा सके, इस दलील पर कि कच्चे अनानास का उपयोग कटे हुए अनानास के निर्माण में किया गया था। निर्धारिती की याचिका को बरकरार रखते हुए, इस न्यायालय ने ऐसे मामलों में परीक्षण निम्नानुसार निर्धारित किए:

"आम तौर पर प्रचलित परीक्षण यह है कि क्या उत्पादित वस्तु को व्यापार में सौदा करने वालों द्वारा उसके निर्माण में शामिल वस्तु से अलग माना जाता है। आम तौर पर,

निर्माण एक या अधिक प्रक्रियाओं का अंतिम परिणाम होता है जिसके माध्यम से मूल वस्तु को पारित किया जाता है। प्रसंस्करण की प्रकृति और सीमा एक मामले से दूसरे मामले में भिन्न हो सकती है और वास्तव में प्रसंस्करण के कई चरण हो सकते हैं और शायद प्रत्येक चरण में विभिन्न प्रकार की प्रसंस्करण हो सकती है। प्रत्येक प्रक्रिया के साथ, मूल वस्तु अनुभव करती है एक परिवर्तन। लेकिन यह केवल तब होता है जब परिवर्तन, या परिवर्तनों की एक श्रृंखला, वस्तु को प्रिंट में ले जाती है जहां व्यावसायिक रूप से इसे मूल वस्तु के रूप में नहीं माना जा सकता है, बल्कि इसके बजाय एक नए और विशिष्ट लेख के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसका निर्माण किया जा सकता है। जहां मूल वस्तु और प्रसंस्कृत वस्तु के बीच पहचान में कोई आवश्यक अंतर नहीं है, वहां यह कहना संभव नहीं है कि एक वस्तु का उपभोग दूसरे के निर्माण में किया गया है। हालाँकि इसमें कुछ हद तक प्रसंस्करण किया गया है, फिर भी इसे अपनी मूल पहचान बरकरार रखते हुए माना जाना चाहिए,

पक्षकारो द्वारा हमारे सामने बड़ी संख्या में मामले रखे गए हैं, और उनमें से प्रत्येक में एक ही सिद्धांत लागू किया

गया है: क्या मूल वस्तु का प्रसंस्करण व्यावसायिक रूप से अलग और विशिष्ट वस्तु अस्तित्व में लाता है? कुछ मामले जहां इस न्यायालय द्वारा यह माना गया कि एक अलग वाणिज्यिक लेख अस्तित्व में आया था, उनमें अनारखान मेहबूब कंपनी बनाम बॉम्बे राज्य और अन्य (जहां कच्चे तंबाकू का निर्माण बीड़ी पट्टी में किया जाता था) शामिल हैं। ए हाजी अब्दुल शुक्र एंड कंपनी बनाम मद्रास राज्य (कच्ची खाल और खाल अलग-अलग भौतिक गुणों वाली सजी-धजी खाल और खाल से अलग वस्तु होती है)। मद्रास राज्य बनाम स्वास्तिक तंबाकू फैक्ट्री (कच्चे तंबाकू को चबाने वाले तंबाकू में बनाया जाता है) और गणेश ट्रेडिंग कंपनी करनाल बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, (धान की भूसी निकालकर चावल बनाया जाता है)..."

इसमें कोई संदेह नहीं है कि अनानास फल जब टुकड़ों में परिवर्तित हो जाता है तो वह अपनी पहचान नहीं खोता है या नया उत्पाद नहीं बन जाता है। इन दोनों को व्यापारिक क्षेत्र के साथ-साथ आम बोलचाल में भी अनानास के नाम से जाना जाता है। यहां पर यह मामला नहीं है।

9. चिरंजीत लाल आनंद बनाम असम राज्य एवं अन्य, 1985 ए.आई.आर. एस.सी. 1387 मामले में इस न्यायालय के एक निर्णय से

उत्तरदाताओं द्वारा काफी समर्थन मांगा गया था। वह मामला 'खुर पर मांस' नामक वस्तु से संबंधित था। उस मामले में डीलर ने असम राज्य के भीतर केंद्रीय रिजर्व पुलिस इकाइयों को 'खुर पर मांस' की आपूर्ति के लिए एक निविदा प्रस्तुत की थी। उस मामले में, खुर वाले मांस की खरीद के लिए डीलर का मूल्यांकन किया गया था, जो मुख्य रूप से सेना द्वारा 'जीवित बकरी' के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला नाम है। डीलर का तर्क यह था कि चूंकि मीट को असम अधिनियम द्वारा बिक्री कर से छूट दी गई थी, इसलिए 'मीट ऑन होफ' को भी मूल्यांकन से छूट दी जानी चाहिए। इस अदालत ने उस मामले के विशिष्ट तथ्यों पर विवाद पर विचार करने के बाद माना कि खुर पर मिलना भी छूट के दायरे में आएगा और उच्च न्यायालय से असहमत होकर मूल्यांकन को रद्द कर दिया। हमारे विचार में, उस निर्णय में प्रतिपादित सिद्धांत को केवल उस मामले के तथ्य पर लागू किया जाना चाहिए क्योंकि उस मामले में शामिल सामान 'मीट ऑन हूप' था और मीट को अधिनियम के तहत मूल्यांकन से छूट दी गई थी। इसलिए, वर्तमान मामलों पर निर्णय लेने में केवल उस मामले के तथ्यों के आधार पर लिए गए निर्णय पर भरोसा करना उचित नहीं होगा। यहां बकरियों और भेड़ों को वध करने की एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, और फिर उक्त प्रक्रिया में बकरी के सेवन से मांस, खाल और त्वचा अस्तित्व में आती है, अंतिम उत्पाद मूल माल से पूरी तरह से अलग होता है। इसलिए, उच्च न्यायालय ने यह मानने में गलती की कि बकरी और

मांस एक ही हैं और बकरियों को मांस में परिवर्तित करने में कोई खपत शामिल नहीं थी। उच्च न्यायालय ने ऐसा कहकर मामले को उलझा दिया कि "बिक्री के लिए रखा गया मांस अभी भी बकरी और भेड़ का है"। इस बात पर कोई विवाद नहीं करता कि मांस बकरी और भेड़ का है। देखने वाली बात यह है कि क्या मांस और बकरा एक ही हैं। उच्च न्यायालय उस समय गलती में पड़ गया जब उसने मामले के तथ्यों पर चर्चा करते समय "बकरी का मांस" अभिव्यक्ति का प्रयोग किया।

10. परिणामस्वरूप, हम उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करते हैं, इन अपीलों को स्वीकार करते हैं, न्यायाधिकरण के आदेश को बहाल करते हैं, लेकिन मामले की परिस्थितियों में लागत के बारे में कोई आदेश नहीं देते हैं।

पी.एस.एस.

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।